[Shri Bhagwat Jha Azad]

Member from the D. M. K. Party referred about Indo-Ceylon agreement. Under this agreement we have also got persons from Ceylon. Upto-now, we have got about 13,000 and odd—14,000 round about. Most of them have gone to their old places. They were brave people and they did not ask much assistance from us. Still we have got a Rehabilitation Bank with the headquarters in Madras. And we shall see that whatever possible assistance is to be given to them is given to them. Further assistance will be given to them as and when they need it.

Now I come to the Dandakaranya.. This is one of the best projects. We have reclaimed areas measuring about 1.22 lakhs. We have opened about 264 villages which are for displaced persons and 61 for the tribals. Whatever we develop, a certain percentage is fixed—25% for being given to the tribal people in that area. We give them the developed facilities We have done something in Dandakaranya. It is unfortunate some members said something about the Chief Administrator. and made some personal charges against him. I have seen from the records that there is no such thing against our able Chief Administrator. He has done an excellent work. I would say that this is one of the projects which has been acclaimed and appreciated not only by Government but all people from different parts of India. Even the Minister from West Bengal appreciated that. I am prepared to invite Shri Kachwai and other members who want to see it to go there and see for themselves to know as to the good work that we are doing in Dandakaranya. And we shall be glad to have their advice for further improvement if any. Now I would like to say a word about repatriates from Burma. We have 1,78,500. So far, 51,000 families have come from Burma and we expect about 1500 families in 1970-71. We are giving them the relief facilities; we give them grants; we also put them in camps. We shall try to do our best to settle them properly.

My last point is this. Shri Metha mentioned about Tabela. There are about 145 units in Tabela at Bhavnagar. They want their compensation to be given by way of properties wherever they are living. There was a difficulty about the question of giving them property. Now it has been established that these properties belong to Gujarat Government. We have written to the State Government about assessment and valuation. I would request him also to try and persuade them to furnish the information. The moment it is received, we shall try and process it to the best advantage and facility of the DPs.

18 hrs.

SHRI G. VENKATASWAMY: What about the IDPL strike?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: The hon. Minister will cover that in his reply tomorrow. I hope it will be possible to persuade the management to come to some settlement by tomorrow. We will not allow the hon. member to go on fast.

I am grateful to hon. members for the attention paid to problems both on the labour and rehabilitation side. There are many points which I have not been able to touch. These can be dealt with later.

I apologise to Shri Biswas.

SHRI J. M. BISWAS: I also apologise to him.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: We are good friends outside and we are young friends too. As he feels about so many things, I also feel about them. So we shouted at each other. Minus this, I am thankful to all the members for their kind attention.

SHRI SHEO NARAIN (Basti): About *Samachar Bharati*, he has not said anything.

SHRI K. N. PANDEY: I want to ask a simple question.

Mr. CHAIRMAN: Tomorrow.

MATTER UNDER RULE 377—*Contd.*

BEATING BY POLICE OF SOME MPS AND SSP DEMONSTRATORS ON 6.4.70—*Contd*

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सदन में

6 अप्रैल, 1970 को हमारी ओर से शानदार जवाब प्रस्तुत करने के लिए सदन के सभी पक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। मैं सदन को उस दिन एक राजनीतिक दल के लगभग सभी नेताओं और कार्यकर्त्ताओं पर हुए पूर्व निर्धारित और पूर्व नियोजित बर्बर हमले की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बातें बतलाना चाहता हूं।

गृह मन्त्री और जिला मजिस्ट्रेट की बात-चीत में मैंने यह कहा था कि संसद् भवन के आस-पास के इलाके में लगे निषेधात्मक आदेशों को तोड़ने का संसोपा का इरादा नहीं है। हालांकि हम संसद् भवन के सामने प्रदर्शन करने के नागरिकों के अधिकार पर ऐसे आदेशों को अनुचित पाबंदी मानते हैं। मैंने गृहमन्त्री और विशेषकर जिला मैजिस्ट्रेट से यह भी अनुरोध किया कि हम लोगों को पटेल चौक पर अपने जलूस को विसर्जित करने और राष्ट्रपति को अपना मांग पत्र देने के पहले वहां एक सभा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट श्री अरोड़ा ने पांच अप्रैल की रात में परेड ग्राउण्ड में हमसे यह स्पष्टतः कहा कि हम लोग पटेल चौक में सभा कर सकते हैं, यद्यपि इसके लिए वे कतिपय कारणों से ही लिखित अनुमति नहीं दे सकते। यहां तक कि उन्होंने साढ़े 11 बजे रात में मुझ से मेरी हस्तलिपि में वाजाप्ता अनुमति के लिए एक आवेदन-पत्र मांगा और लिया।

इतनी बात-चीत हो जाने पर 6 अप्रैल को किसी तरह की घटनायें घटेंगी, ऐसी आशंका हमें नहीं रह गई थी और इसीलिए हमने प्रदर्शनकारियों को अपने बच्चे गोद में और लड़कों को भी साथ लाने की इजाजत दी। कुछ क्षेत्रों में ऐसा कहा जा रहा है कि संसोपा ने संसद् पर हल्ला बोलने की योजना बनाई थी। इसी कारण प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस जहरीले झूठ से ज्यादा हास्यास्पद बात की कल्पना नहीं की जा सकती। जिन लोगों का पुलिस को बचाने में कोई स्वार्थ नहीं है, वे लोग यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करेंगे कि आदिवासी लोग अपनी परम्परागत वेशभूषा के अंग के रूप में धनुष और तीर को उसी तरह साथ रखते हैं, जिस तरह सिख लोग और गुरखा लोग अपने कृपाण और खुखरी हमेशा साथ लिए रहते हैं। यदि अधिकारी परम्परागत वेशभूषा को पहनना आपत्तिजनक समझते तो लाल किले के सामने परेड ग्राउण्ड से जुलूस चलते समय ही उसे रोका जा सकता था। उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे समझते थे कि धनुष और तीर लेकर चलने से किसी तरह के सशस्त्र प्रहार का इरादा नहीं झलकता। पटेल चौक में किसी भी समय आदिवासियों का पुलिस वालों से आमना-सामना नहीं हुआ।

18.05 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

पटेल चौक पर जलूस पहुंचने के आधा घन्टा पहले मधु लिमये और मनी राम बागड़ी ने पुलिस से बातचीत की और पटेल चौक में सभा करने की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया। पुलिस के कहने पर हम लोगों ने अशोक रोड पर विंडसर प्लेस की तरफ मंच बनाने के बजाय पंजाब नेशनल बैंक बिल्डिंग प्लेस की तरफ मंच बनाया। दस बजे से ही लाउड स्पीकर आदि लगाने का काम चल रहा था और जलूस आने पर उसे मंच से जोड़ा गया। मधु लिमये के कहने पर ही पुलिस पटेल चौक से अपना घेरा हटा कर पार्लियामेंट हाउस की तरफ पार्लियामेंट स्ट्रीट पर और विंडसर प्लेस की तरफ अशोक रोड पर पीछे हटी।

सभा की कार्यवाही आदिवासी नृत्य और गान से शुरू हुई। रवि राय, मधु लिमये और जे० एच० पटेल उसके बाद हमारे मांग पत्र की एक प्रति अध्यक्ष को देने और उनसे सभा को

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

सम्बोधित करने की प्रार्थना करने के लिये संसद् भवन जाने को रवाना हुए।

इसी समय कुछ लोगों ने हमें सूचना दी कि संसद् भवन वाले तरफ पटेल चौक पर के पुलिस घेरे के पास कुछ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कुछ तनाव और हलचल हो रही है। पार्टी के कुछ नेता तुरन्त उस तरफ गये और इन प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस के बीच में दीवाल की तरह खड़े हो गये। उन्होंने निजी प्रभाव का इस्तेमाल करके इन प्रदर्शनकारियों को शान्त किया और पुलिस से भी कहा कि वे झगड़ा न उकसायें। रवि राय, मधु लिमये, जे० एच० पटेल, राम सेवक यादव, रामानन्द तिवारी, कमलेस और स्वयं मैंने हस्तक्षेप किया और किसी तरह का उकसावा और झगड़ा होना रोकने की कोशिश की।

फ्रांस और जापान जैसे सभ्य देशों में, फ्रांस में मई, 1967 में और जापान में राष्ट्रपति आइजन हावर के आगमन के समय 1959 में, अर्ध बगावत जैसी परिस्थितियां पैदा हुईं। इन बगावतों का संगठन करने वाले समूह अहिंसा के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध नहीं थे। और न ही इन समूहों के नेताओं ने उकसावा रोकने और जनता को शान्त करने के लिये हस्तक्षेप किया, फिर भी पुलिस ने इन विद्रोही जनों के साथ प्रशंसनीय संयम से व्यवहार किया। आजादी के 23 वर्ष बाद भी देश में कहीं भी इस तरह का संयम नहीं दिखाई देता। 6 अप्रैल को पुलिस के हस्तक्षेप और बल प्रयोग का कोई कारण नहीं था। लोगों का जमाव न गैर कानूनी था, न ही लोग हिंसक हो रहे थे। इन जनों के नेतागण स्वयं हस्तक्षेप कर रहे थे ताकि कोई अवांछनीय घटना न घटे और इस पर भी केवल सिपाहियों ने ही नहीं, बल्कि पुलिस अधिकारियों ने अपना पूर्व निर्धारित हमला, परिस्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर रहे नेताओं को ही अपना प्राथमिक शिकार बना कर, शुरू कर दिया। वस्तुतः दो लाठी प्रहार हुए और आंसू गैस दो बार छूटी और जिस तरह की दृढ़ता और क्रूरता पुलिस ने दिखाई, उससे यह जाहिर था कि उनका इरादा हममें से कुछ को खत्म करने का था।

कम से कम चार पुलिस सिपाही और दो पुलिस अधिकारी जिनके पीछे दर्जनों सिपाही रहे होंगे, मुझ पर लाठियां बरसाते रहे और जब हमारे कुछ साथी मेरी मदद को पहुंचे, तब भी उनकी लाठियां चलती रहीं। मुझे जब मेरे कुछ साथी किसी सुरक्षित स्थान में ले जाने की कोशिश कर रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर बतला रहे थे कि मैं कौन हूं, तब भी मुझको पुलिस के घेरे के भीतर घसीटा गया और मुझ पर लाठियां चलाना जारी रखा गया। करीब एक घन्टे तक मुझे अस्पताल नहीं ले जाया गया और पुलिस अधिकारी इस सारे समय मुझ पर तानाकशी करते रहे और मुझे तथा मेरे साथियों को कहते रहे कि जो चाहो करो। उनमें से एक ने जिसने अपना नाम मारवाहा बतलाया, बहुत अमानवीय व्यवहार किया और जब तक मेरे साथी गाड़ी से उतर न जायें तब तक मुझे अस्पताल ले जाने से भी इन्कार किया। इन साथियों को भी काफी चोट लगी हुई थी, और अगर उस समय वे मेरा बचाव करने के लिये न आते तो इस समय यहां खड़े रहने के लिये मैं नहीं पहुंच पाता।

इस संगठित हमले में कोई एक हजार से डेढ़ हजार तक हमारी पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिनमें हरिजन और आदिवासी औरतें भी शामिल हैं, बुरी तरह से पुलिस ने पीटा।

आधुनिक भारत के इतिहास में मुझे इस तरह की कोई दूसरी घटना नजर नहीं आती जब कि सरकार के राजनीतिक विरोधियों पर सम्पूर्ण रूप से हमला किया गया हो। पुलिस

द्वारा पीटे जाने वाले लोगों में कई राज्य शाखाओं के अध्यक्ष और भूतपूर्व अध्यक्ष, मंत्री और भूतपूर्व मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, प्रधान मंत्री और राष्ट्रीय समिति के सदस्य, जिला पार्टियों के अध्यक्ष और मंत्री और कई संसद् सदस्य तथा विधान सभाओं के सदस्य थे। बहुत से लोगों की हड्डियां टूटीं। ज्यादातर आहत लोग चिकित्सा के लिये अस्पताल भी नहीं जा पाये। क्योंकि जो लोग अस्पताल पहुंच गये थे, उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर रही थी। हमारे एक साथी श्री बिहारी सिंह लाठियों से लगी चोटों के फलस्वरूप मर गये और उनकी लाश हमें मिली, लेकिन मुझे पर्याप्त कारण प्राप्त हैं जिन से यह यकीन होता है कि पुलिस की लाठियों से कई और लोगों की भी जानें गयीं और उनकी लाशें गायब की दी गईं। तमाम लोग अभी भी लापता हैं और सरकार ने अब तक कोई पूरी रिपोर्ट नहीं दी है। प्रधान मंत्री ने उच्च न्यायाधीश द्वारा जांच करवाने का वायदा किया था लेकिन अब तक इस कार्य के लिये कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। क्या यह घोषणा सदन में सरकार की हार न हो, केवल इसलिये की गयी थी ? यह भी विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि पुलिस अधिकारी अखबारों में लेख और चिट्ठियां छपवाने में लगे हुए हैं। जिनमें पुलिस की क्रूरता और हिंसा का बखान किया गया हो।

श्री के० के० शाह, श्री बलीराम भगत, श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री ललित नारायण मिश्र और कई अन्य संसद् सदस्यों तथा दूसरे लोगों ने हमें बतलाया है कि 6 अप्रैल की घटनाओं के पीछे कोई षडयन्त्र था। हालांकि हर व्यक्ति का साजिश के बारे में अपना मत है। संसद् भवन से कुछ ही कदम आगे इस तरह के प्रबल हमले बिना कुछ उच्च पदासीन लोगों के प्रोत्साहन या राय से हो सकते हैं, यह मैं नहीं मान सकता।

सदन को इस घटना के निहितार्थों पर विचार करना चाहिये, पटेल चौक पर ऐसे लोगों का जलूस आया था, जिनका दृष्टिकोण लड़ाकू है, पर जो लोग निःसंदिग्ध रूप से महात्मा गांधी और डा० राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के सिद्धान्त से बंधे हुये हैं। इस पार्टी के नेता कायरों की तरह अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने खुद हस्तक्षेप किया और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच दीवाल बनाकर खड़े हो गये ताकि कहीं कोई उकसावा और झगड़ा न हो। फिर भी इस पार्टी को, इसके नेताओं को और इसके प्रदर्शनकारियों को पुलिस की हिंसा और बर्बरता का शिकार बनाया गया। यह ऐसी घटना है, जिस पर सारे देश का और इस संसद् का ध्यान जाना चाहिये और न केवल अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, बल्कि कानून और व्यवस्था के पूरे प्रशासनिक ढांचे में और जन समूहों के प्रति पुलिस के व्यवहार में सुधार लाने के कदम उठाये जाने चाहिये ताकि भारत भी सचमुच सभ्य देशों की कतार में आ सके।

अन्त में एक शब्द और। जिन दिनों मैं अस्पताल में था, मुझे सारे देश से सैकड़ों लोगों की चिट्ठियां और तार से संदेश प्राप्त हुए। अध्यक्ष महोदय भी मेरी स्वास्थ्य कामना करने आये। ऐसे ही हजारों जनता के लोग, मजदूर और किसान, काबीना के मंत्री, राजदूत, कूटनीतिज्ञ और सभी राजनीतिक दलों के नेता और संसद् सदस्यों ने भी मेरी स्वास्थ्य कामना की। आप और इन सभी लोगों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करता हूं।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : जो बातें माननीय सदस्य ने कही हैं, उनके बारे में इस सदन में पहले चर्चा हो चुकी है।

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

दो तीन बातें हैं, जिनका मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं।.....

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : मंत्री महोदय किस चीज पर बोलने जा रहे हैं ? क्या कहने जा रहे हैं ? इनको जो कुछ कहना था, इन्होंने उस दिन कह दिया था। जार्ज फरनेन्डीज साहब उस दिन यहां नहीं थे, इस वास्ते उनको आज मौका दिया गया है। लेकिन मंत्री महोदय तो जो कहना चाहते थे, उसको कह चुके हैं।

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi) : Will there be a debate on this ? Then you should fix some time for it because all of us want to participate in it, as there are other instances of firing also in Delhi. Section 144 was imposed on this House also, on this compound, but surreptituously they have changed the order the other day. They have not come here honestly with clean hands. I feel very strongly about it.

MR. DEPUTY SPEAKER : You have made your point. Let us hear the minister.

SHRI M. L. SONDHI : Every time I go home thinking that I have done some thing, but on the next day no mention is made about it and it never comes on the agenda. Instead, the magistrate issues another order saying that section 144 applies to the approach roads. I want to know whether the Home Ministry directed the District Magistrate to impose section 144 on this House and if so, will they come here and apologise for it ? (*Interruptions*).

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peermade) : We are supposed to have a debate on the West Bengal Bill from 6 O'clock. For that we were scheduled to sit till 8 O'clock. Now, will we be sitting till 10 O'clock ?

MR. DEPUTY SPEAKER : Now this is the issue before the House.

SHRI VASUDEVAN NAIR : It is not there on the agenda.

श्री मधु लिमये (मंगेर) : जार्ज फरनेन्डोज साहब ने बयान अध्यक्ष की सम्मति से किया है। मंत्री महोदय के द्वारा आज बयान करने की कोई जरूरत नहीं है। कल करें। सोलह दिन तक उन्होंने बयान नहीं दिया है, आज बयान करने आ गए हैं। कल बयान करें।

MR. DEPUTY SPEAKER : It is true it is not there on the agenda. But the Speaker has given special permission to Mr. George Fernandes to make a statement under rule 377. But rule 377 does not preclude a small discussion.

The point raised by Mr. Sondhi is perfectly valid. You have made your point. If the minister wishes, he can reply.

SHRI RANGA (Srikakulam) : My point of order is this. It is the privilege of the Speaker or the Chairman to allow anyone of us to make a statement on an important occasion like this. We have only to obtain the previous permission of the Chairman to make the statement. But that does not necessarily mean that the Speaker has to call upon the government also to make a reply. That is the first point. Secondly, when this question had been discussed earlier the House was unanimous on that day on this point and we got the impression that the government was going to appoint an inquiry and it is for that inquiry to take into consideration what all has been said today by my hon. friend, Shri George Fernandes as well as the other statements that have been made here, together with the reply or the statement made by the Home Minister on that day and then to make a report. Thereafter, it would be open to the government to make a statement. But to day to ask him to make a statement, or allow him to make a statement, would be entirely out of order, would not be proper at all for this House because he can only comment on the facts that have been presented whereas we want a judicial inquiry.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : I fully support Professor Ranga because, in this particular case, Shri George Fernandes was beaten mercilessly ; practically he was being

liquidated. He was not present in the House when so many things were said and the nasty letter published in various newspapers. Naturally, when he came here he made a factual statement under rule 377 with the permission of the Speaker, not in defence of the struggle or that procession but a factual statement. What he has demanded is only an inquiry. In spite of the Solemn assurance given by the Prime Minister on the floor of the House—before the Home Minister could speak she intervened and sprang a surprise by announcing that they are going to have a judicial inquiry—no judicial inquiry is being instituted either by a High Court Judge or a Supreme Court Judge. Now the hon. Member has made a statement. The whole matter has to go before the judicial inquiry which is about to be appointed. It is a shameless thing that a judicial inquiry has not been instituted till today. It is open to the Minister to deny or accept what Shri George Fernandes has said. In that case, it would again become a controversy. Now he is the aggrieved person and he has made the statement. The Minister has not got a lathi or tear gas. He has to face this statement. Naturally, he has to make a statement. So, Sir, I would request you to ask the Minister not to make a statement today; let him think over the matter and make a statement tomorrow.

MR. DEPUTY SPEAKER: Would you like me to acertain from the Minister now whether he would like to say anything on this limited question of a judicial inquiry?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I was saying the same thing when the hon. Member interrupted me. I was going to say something about the judicial inquiry. But then hon. Members got so impatient that they did not allow me to proceed. Only as a point of personal explanation I want to say—(*Interruptions*).

SHRI M. L. SONDHI: As long as section 144 is there, he can summon police. We cannot even meet. He sommoned police to beat Shri George Fernandes that day. Today he can summon police to beat all of us. The Speaker must assert on behalf of the Members here and see to it that section 144 is withdrawn. I hold the Minister responsible for this. It is breach of our privileges. Otherwise, what is the point or value of having our rules of procedure? That day Shri George Fernandes was beaten up. Now the Minister has become so arrogant and so impertinent that he does not, even on this occasion, tell us why Section 144 was imposed in Parliament House, not outside but in the compound of Parliament. What then is the use of this provision which entitles the Speaker alone, and only the Speaker, to decide what will go on inside the House? He may come here and set up his own rule here. It is not for Mr. Shukla to decide. It is a sovereign Parliament.

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Sondhi, please sit down.

SHRI M. L. SONDHI: I want to know what is happening? Why Section 144 is imposed on us, Sir. He comes out with a personal explanation. He should not be allowed to make personal explanation.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North East): Are we to be at the mercy of lunatics? How long are we going to tolerate it?

SHRI M. L. SONDHI: I do not want to reply to Mr. Mukerjee because he is my elder. I respect him.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara): Would you respect the wishes of the House and sit down?

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Sondhi, would you kindly listen to me?

SHRI M. L. SONDHI: I have been urging for one year. This whole incident would not have taken place but for the abuse of the jurisdiction on the part of the Minister.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: The only point for me to make is that it was not I that told Mr. Fernandes that there was any conspiracy in this matter.

श्री मधु लिमये : अब मुझे भी व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना है। आपने इन्हें इजाज़त दी है तो मुझे भी दीजिए।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Now with your permission I want to say as soon as the decision to appoint a Commission of Enquiry was announced in the House we immediately got in touch with the Chief Justice of India and requested him to suggest the names of a few serving judges of the High Court who could be appointed to conduct this enquiry. He suggested three names—two were ICS judges and one was a non-ICS judge. We thought that it would be better if we appointed a judge who was a non-ICS officer and, therefore, we have now taken a decision and a notification has been issued or is being issued today to appoint a Commission of Enquiry consisting of Shri Justice Kuppuswami Alladi, Judge, High Court, Andhra Pradesh, to enquire into the following matters :

(a) The course of events arising out of the procession taken out by the Samyukta Socialist Party in New Delhi on the 6th of April, 1970, and particularly, the incidents in and around the Patel Chowk area involving use of force resulting in injuries to several persons, including some Members of Parliament, and the death of Shri Behari of Barabanki, alleged to have been caused as a result of the use of such force ;

(b) the justification for the use of force by the police and the extent thereof ; and

(c) any other matter having relevance to the above. The Commission is expected to make its report to the Central Government within 4 months.

The Commission will have all requisite powers under the Commission of Inquiry Act, 1952.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISRA) :—On a point of personal explanation.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE (Ratnagiri) : On a point of order, Sir. Is it not the rule that the Speaker's permission has to be had before a Member is allowed to make a personal explanation ? On various occasions we ourselves have suffered. We had to write to the Speaker and the Speaker had to approve of what we were going to say. But you are allowing Minister after Minister to make personal explanations.

MR. DEPUTY SPEAKER : The Speaker had allowed Shri George Fernandes to raise this under rule 377. Under rule 377 questions are raised and a reply is called for. It is under that rule that when a Member has made a statement the Minister makes a statement.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE : I was referring to Shri L. N. Misra who is rising on a point of personal explanation.

SHRI L. N. MISHRA : My name is mentioned there.

SHRI A. K. SEN (Calcutta—North-West): Apart from matters of controversy, may I congratulate and express our jubilation on seeing Shri George Fernandes here amongst us and having made a statement. I hope, in future no Member here will be subjected to this ordeal.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, श्री वी० सी० शुक्ल जी ने कहा कि मैंने जार्ज फरनेन्डीज से कोई ऐसी बात नहीं की। जार्ज फरनेन्डीज ने अभी जो बयान पढ़ा, उसमें यह नहीं कहा था कि मुझको कहा गया, उन्होंने कहा था कि हम को कहा गया और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्री बलिराम भगत और श्री वी० सी० शुक्ल ने स्वयं कई लोगों को सामने मुझ से यह कहा कि षडयन्त्र था, इसमें हमारी सरकार तकरीबन खत्म होने वाली थी। तब मेरी पत्नी ने कहा कि आपकी तो सरकार जाने वाली थी, लेकिन इन लोगों की तो जान जाने वाली थी। अब इनका यह कहना कि मैंने फरनेन्डीज को नहीं कहा—फरनेन्डीज ने यह नहीं कहा कि मुझको कहा, उन्होंने कहा था—these people told us—इसलिये मैं इसका स्पष्टीकरण करना चाहता था ताकि यह रिकार्ड पर आ जाय।

MR. DEPUTY SPEAKER : Now that an inquiry commission has been appointed, would all that not be a subject of the inquiry commission? Why should you make any more statements here now ?

श्री ल० ना० मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि भाई जार्ज ने कुछ ऐसी बात कह दी है जिसका हमें खण्डन करना पड़ता है। मैं विलिंगडन अस्पताल में जार्ज को दो बार देखने अवश्य गया था। मैंने उनसे उनके स्वास्थ्य की बात की और शरीर पर ध्यान देने का आग्रह किया। षडयन्त्र या और कोई बात मैंने उनसे नहीं की। मैं उनकी इस बात का खण्डन करता हूं।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA rose—

श्री मधु लिमये : अब यह काउन्टर रिप्लाई कब तक चलेगा ? इन्होंने कहा, हम ने कहा, अब इस मामले को खत्म करिये। जो लोग जार्ज से मिलने गये और क्या-क्या कहा, सबके सामने है।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I emphatically deny that I have said those words to Shri Madhu Limaye. I have not said those things.... (*Interruption*).

MR. DEPUTY SPEAKER : Now that the inquiry commission has been appointed, let us close this matter.

---

18. 34 hrs.

WEST BENGAL STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

THE MINISTER OF STATE IN EHE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I move* :

> "That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of West Bengal to make laws, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The House will recall that under the Proclamation issued by the President, the President assumed the powers of the State Legislature. That would be exercised by and under the authority of Parliament. We know of the heavy schedule of Parliament and we also know that it will be impossible for Parliament to find time to undertake legislature for the State of West Bengal. Therefore, as has been done many times earlier whenever unfortunately President's rule had to be imposed on various States of the Union when popular governments could not function in those States for one reason or another, we have to move this Bill here to authorise the President to enact laws on behalf of the State Legislature of West Bengal.

We have also added a system by which a Consultative Committee is formed to advise the President on enactment of such laws to enable the hon. Members who serve on that Committee to raise various other points which are non-legislative in nature. We want as much of popular element associated with the administration even in President's rule so that we acquaint all hon. Members about the various problems that the State administration faces there during President's rule. Therefore, we also have a system by which the hon. Members can raise many points during the deliberations of this Committee and all these points, as far as possible, are answered in the session of the Committee itself and if the answers cannot be given in the session of the Committee, then the Members are sent information later on by the Government.

Sir, there is not much for me to say as far as this particular matter is concerned. I would commend this particular Bill to the acceptance of the House. Sir, before I sit down I would state that the membership of this Committee is proposed to be 60 as it was when the State of West Bengal came under President's rule earlier and I think this is a good size for the Committee in which we can get the representation of all the Groups and Parties that function in this House and the Upper House. Therefore, I hope the House will pass this Bill.

*Moved with the recommendation of the President.